GENERAL INSURANCE EMPLOYEES' ALL INDIA ASSOCIATION

(Affiliated to Trade Union International)
Regd.No.8531
e-mail address: - gieaia1971@yahoo.com,
Sterling Cinema Building, Third floor,
No.65, Murzban Road, Fort, Mumbai –400001
Working Office: 15-16, Scindia House, KG Marg, New Delhi-110001.Phone No.011-43556959

CLASS 3-4 WING
CHAIRMAN : BINOY VISWAM, EX MP
President : AMARJEET KAUR
Working President : R.SRINIVASAMURTHY
General Secretary: TRILOK SINGH
E-Mail:trilokpundeer@gmail.com
Addl. General Secretary : A.KUMARAVELU
E-Mail: kumargieu222408@gmail.com

CLASS 1 WING
CHIEF PATRON : BINOY VISWAM, EX MP
CHAIRPERSON : AMARJEET KAUR
President : AR ANANDA JAWAHAR
E-Mail: anandjawhar@gmail.com
Working President : D VIJAY KUMAR
Secretary General: DARSHAN KR. WADHWA
E-Mail:darshankwadhwa@gmail.com

दिनांक : 04/07/2025

प्रिय साथियो,

सार्वजनिक क्षेत्र और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु 9 जुलाई 2025 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में सहभागिता का आह्वान

भारतीय श्रमिक वर्ग ने अपने सतत संघर्षों और अपार बलिदानों के माध्यम से देश में ट्रेड यूनियन अधिकारों को प्राप्त करने में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं संघर्षों की बुनियाद पर सार्वजनिक क्षेत्र (पब्लिक सेक्टर) का विकास हुआ, जो जनता के धन — अर्थात् पब्लिक एक्सचेकर — से निर्मित हुआ। परिणामस्वरूप, विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में विशाल सार्वजनिक उपक्रम स्थापित हुए, जो देश के आधुनिक मंदिर बन गए।

इन सार्वजनिक क्षेत्रों ने न केवल आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि लाखों शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए, देश का विशाल बुनियादी ढांचा तैयार किया और अपने अमूल्य योगदान से आर्थिक विकास में राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बने।

वित्तीय क्षेत्र में भी प्रारंभ में बैंक और बीमा कंपनियाँ बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के नियंत्रण में निजी हाथों में थीं। इस कारण, जनता की बचत और सार्वजनिक धन निजी स्वार्थों की दया पर निर्भर हो गया, जिसका उपयोग राष्ट्रीय विकास के बजाय पूंजीपति साम्राज्य के विस्तार में होने लगा। **यही कारण था कि "राष्ट्र निर्माण" के उद्देश्य से बैंकों और बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की ऐतिहासिक माँग उठी, जो संविधान में निहित समाजवादी और समान विकास के आदर्शों के अनुरूप थी।**

यह अत्यंत **दुर्भाग्यपूर्ण** है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने वाली इन नीतियों को और सशक्त करने के बजाय वैश्वीकरण की नीतियों को थोप दिया गया, और तब से सार्वजनिक क्षेत्र पर हमलों में लगातार वृद्धि हुई। **इसी प्रकार, हमारे बीमा उद्योग में भी हमने निजीकरण की धमकियों, 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अनियंत्रित निजी कंपनियों के प्रवेश और उनके अनैतिक तौर-तरीकों, कर्मचारियों की संख्या में तेज कमी के कारण असहनीय कार्यभार, उसके परिणामस्वरूप अनैतिक और अवैध कार्य घंटे जिनके लिए समुचित लाभ नहीं मिले, पिछले चार्टर के बाद से वेतन पुनरीक्षण में देरी और वर्तमान पुनरीक्षण अभी तक लंबित जैसे कई गंभीर संकटों का सामना किया है।**

फिर भी इन कंपनियों ने सरकार को करोड़ों रुपये के डिविडेंड का भुगतान किया है, साथ ही आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कई अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है। लगभग 20,000 पद (कक्षा I, II और III) रिक्त रहने के बावजूद विपरीत परिस्थितियों और गंभीर स्टाफ की कमी का सामना करते हुए भी PSGICs के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अद्वितीय निष्ठा और दृढ़ता दिखाई है, और PSGICs ने सराहनीय लाभ अर्जित किए हैं। इसके बावजूद यह दुखद है कि उनकी न्यायसंगत माँगों पर अभी तक विचार नहीं किया गया।

जारी है --2--

हमें इस बात पर गर्व है कि भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, परंतु इस सच्चाई को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश 127 में से 105वें स्थान पर और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 93वें स्थान पर है।

भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन ने हमेशा मज़दूरों के शोषण का विरोध किया और कठिन संघर्षों से अनेक श्रम अधिकार प्राप्त किए। आज यही अधिकार "श्रम सुधारों" के नाम पर खतरे में हैं। हम उत्पादकता बढ़ाने के पक्षधर हैं, लेकिन यह देखकर निराशा होती है कि अधिक उत्पादकता से कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ा, पर श्रमिकों के वेतन में कोई समानुपातिक वृद्धि नहीं हुई। और भी चिंताजनक बात यह है कि देश की 70% संपत्ति केवल शीर्ष 5% अमीरों के पास है, जबकि निचले 50% लोगों के पास केवल 3% संपत्ति है। पिछले एक दशक में देश में गरीबी 17% बढ़ी है।

साथियो, जिस प्रकार श्रमिक वर्ग ने देश की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी प्रकार आज भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रक्षा करना और जनहितकारी आर्थिक नीतियों को बनाए रखना हमारा समान रूप से महत्वपूर्ण कर्तव्य है। पूरे देश में भारतीय श्रमिक वर्ग निजीकरण, 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और श्रम विरोधी संहिताओं का मजबूती से विरोध कर रहा है, जो दशकों से अर्जित अधिकारों, रोज़गार सुरक्षा और ट्रेड यूनियन स्वतंत्रता को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं।

इसी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, हमारा देशभक्ति से प्रेरित कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय श्रमिक वर्ग के व्यापक संघर्षों के साथ मज़बूत एकजुटता दिखाएँ, और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) के कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनर्स, सेवानिवृत्त साथियों और सभी हितधारकों की न्यायसंगत माँगों को दृढ़ता से आगे बढ़ाएँ।

हमारी प्रमुख माँगें इस प्रकार हैं:
✓ PSGICs में LIC के समान स्तर पर लंबित वेतन पुनरीक्षण का तुरंत समाधान।
✓ 1995 पेंशन योजना का सभी के लिए विस्तार; और तब तक NPS में 14% नियोक्ता अंशदान सुनिश्चित किया जाए।
✓ पारिवारिक पेंशन की दर को समान रूप से 30% किया जाए।
✓ सभी कैडर में पर्याप्त नई नियुक्तियाँ की जाएँ ताकि कुशल संचालन सुनिश्चित हो सके।
✓ लंबित नॉन-कोर लाभों का तुरंत निपटान किया जाए।
✓ PSGICs का विलय कर इन्हें एक सशक्त और संगठित सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के रूप में मजबूती दी जाए।
✓ निजीकरण, 100% FDI, श्रम विरोधी संहिताओं, आउटसोर्सिंग और संविदा आधारित रोजगार का पुरज़ोर विरोध।

साथियो, हम सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से — चाहे वे किसी भी वर्ग, जाति या लिंग के हों — अपील करते हैं कि **9 जुलाई 2025 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल** में पूरे उत्साह और एकजुटता के साथ भाग लें, ताकि अपने अधिकारों की रक्षा की जा सके, न्याय सुनिश्चित हो सके और सार्वजनिक क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित रह सके।

क्रांतिकारी शुभकामनाओं सहित,

त्रिलोक सिंह
महासचिव, GIEAIA

दर्शन कुमार वधवा
महासचिव, GIEAIA (क्लास I विंग)